

Ref: SD/258/259/11/12/2026-27

10.09.2026

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] Mumbai - 400 051 Scrip Code: CANBK
---	--

Dear Sir/Madam,

Subject: Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities – Newspaper Publication

This is in continuation of our earlier intimation letters dated 02.04.2026, 09.06.2026 and 22.07.2026 bearing reference no. SD:570/571/11/12:2025-26, SD:131/132/11/12:2026-27 and SD/195/196/11/12/2026-27 respectively. In this regard, please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Vijayavani (Kannada) published on 10.09.2026 for attention of the shareholders of the Bank regarding Special Window for Transfer and Dematerialisation Requests of Physical Shares.

This is for your information and records.

Thanking You,

Restricted

**Santosh Kumar Barik
Company Secretary**

Secretarial Department
Head Office
112 J C Road, Bengaluru - 560002
Restricted
www.canarabank.bank.in

खबर कोना

डीयू में छात्रों के लिए सुरक्षित आवास को लेकर आपात बैठक की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

सत्य निकेतन में इमारत हादसे के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) के सदस्य ने छात्रों के लिए सुरक्षित और किरायाती आवास की जरूरत पर चर्चा करने के लिए शीर्ष निकाय की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। कार्यकारी परिषद सदस्य मिथुराज धुसिया ने कुलपति योगेश सिंह को लिखे पत्र में कहा कि पांच मंजिला रहियाशी इमारत (जिसमें छात्र पैगंग गेस्ट के तौर पर रहते थे) के ढहने से छात्रों के रहने के लिए सुरक्षित, किरायाती और सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित करने में अधिकारियों की नाकामी उजागर हो गई है। धुसिया ने कुलपति से कार्यकारी परिषद की आपात बैठक बुलाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा का आग्रह किया।

पीजी व किराए के आवासों में रहने वाले छात्रों से बातचीत करेगी पुलिस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

दिल्ली पुलिस ने अपने थानेदारों (एसएचओ) और सहायक पुलिस आयुक्तों (एसपी) को पैगंग गेस्ट (पीजी) और अन्य किराए के आवासों में रहने वाले छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने और उनकी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह निर्देश सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने से सात लोगों की मौत के बाद दिए गए हैं। दरअसल, घटना के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पुलिस और अन्य अधिकारियों को पीजी आवास में रहने वाले छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस को 20 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। आदेश के अनुसार, जिन इलाकों में कालेज, विश्वविद्यालय, छात्रावास और पीजी ज्यादा हैं, वहां के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रहने वाले छात्रों से नियमित रूप से मिलकर बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं।

गोकलपुर मेट्रो स्टेशन तक नाले का निर्माण करेगी सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उत्तर-पूर्वी लोकसभा के कई बड़े नालों का गहन निरीक्षण किया। इनमें खासकर एस्केप नाला एक, बिहारीपुर नाला, बंड नाला और गोकलपुर नाला प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोनिया विहार पुश्ता से जुड़े विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग को गीतांजलि स्कूल वजीराबाद रोड से गोकलपुर मेट्रो स्टेशन तक बरसाती पानी नाले का प्रस्ताव तैयार कर जल्द काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। कपिल मिश्रा उत्तर पूर्वी लोकसभा के मंत्री प्रभारी भी हैं। उन्होंने जलभराव से निपटने के लिए नालों की सफाई व पंपिंग व्यवस्था को और मजबूत करने और इन कार्यों की नियमित निगरानी के सख्त निर्देश भी दिए और कहा कि पानी के ओवरफ्लो होकर रहियाशी क्षेत्रों में घुसने के स्थायी समाधान की ओर बढ़ना है।

डूझू चुनाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूझू) चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। लेकिन इस साल दाखिला लेने वाले प्रथम वर्ष के कई छात्रों के कालेज पहचान पत्र (आइडी कार्ड) अभी तक नहीं बन पाए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि डीयू के प्रथम सत्र के जिन छात्रों को अभी तक आइडी कार्ड नहीं मिला है, वे दाखिला पर्वी दिखाकर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

डूझू के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि जिन छात्रों को अभी तक पहचान पत्र नहीं मिले हैं, वे फीस रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो लगा प्रमाणित पत्र और कोई भी सरकारी पहचान पत्र दिखाकर नामांकन कर सकते हैं। बता दें कि डूझू चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए छात्र पहचान पत्र जरूरी होता है। किसी भी

नई दिल्ली

राजधानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन हादसे पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अवैध निर्माण और गैरकानूनी ढांचों पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से बुधवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में कार्रवाई भी की गई। सीएमओ के बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कार्रवाई प्रभावी तरीके से हो सके। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली के सभी पैगंग गेस्ट (पीजी) और छात्रावासों का सघन निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। जहां भी अवैध निर्माण पाया जाए, वहां तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। रेखा गुप्ता ने भवनों के रिकार्ड खंगालने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा गया है कि संबंधित अवैध निर्माण किस वर्ष किया गया था और उस समय वह किस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसके जरिए अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी पहचान की जाएगी।

राजधानी के अधिकांश इलाकों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत निर्धारित भवन उप-नियमों का घोर उल्लंघन कर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। खुद निगम के अधिकारी भी मामलों के संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। जानकारी के मुताबिक, शाहदरा दक्षिणी जोन के लक्ष्मी नगर के संपत्ति संख्या सीआर-254, सीआर रोड, ललितार्क पर पांच मंजिला रहियाशी भवन का अनधिकृत निर्माण किया गया है। क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता (भवन) के निरीक्षण के

‘भारतीय ज्ञान परंपरा ही विकसित भारत का आधार’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं श्री काशी विद्वत परिषद (दिल्ली प्रांत) के संयुक्त तत्वावधान में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय विद्याओं का पुनर्जागरण 2047’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। विशेषज्ञों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित भारत का आधार बताया। मुख्य वक्ता प्रो रमाकांत पांडेय ने भारतीय भाषाओं को ज्ञान-विज्ञान का भंडार बताया। परिषद के महामंत्री प्रो रामनारायण द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण में परिषद की भूमिका

बताई। विशिष्ट वक्ता प्रो शिवशंकर मिश्र ने भारतीय ज्ञान पद्धति के नैतिक मूल्यों को सामाजिक नीतियों में प्राथमिकता देने की बात कही। विशिष्ट अतिथि विधायक पूनम शर्मा ने भारतीय विद्याओं के पुनर्जागरण को देश के लिए नई दिशा बताया। सत्रों में प्रो विनय पाण्डेय (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), प्रो दिनेश गर्ग (सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय) और प्रो नचिकेता सिंह (प्राचार्य, श्याम लाल महाविद्यालय सांध्य) ने विचार रखे। प्रो. रमेश कुमार पांडेय ने उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने की बात कही। देशभर के सैकड़ों प्राध्यापकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

दल या संगठन की ओर से नामित पर्वी नहीं भरा जाता। छात्र संगठनों के डूझू उम्मीदवार भी बतौर छात्र और अपने संस्थान का उल्लेख करते हुए प्रशासन के सामने अपनी दावेदारी रखते हैं। यह अलग बात है कि पर्वी

Restricted

सत्य निकेतन हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर

दो दिन में 34 अनधिकृत निर्माण ढहाए, 17 संपत्तियां सील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पिछले दो दिनों में अपने 12 क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण की 34 कार्रवाई की और 17 संपत्तियों को सील किया है। इसके अलावा, निगम ने बुधवार को भवन उपनियमों और दिल्ली मास्टर प्लान के उल्लंघन के खिलाफ अभियान के तहत 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए और चार ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में लड़कों के लिए संचालित एक पीजी इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद निगम ने यह कार्रवाई तेज की है। निगम ने सत्य निकेतन में जर्जर इमारत को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद इमारत जर्जर हो गई थी और उसे खतरनाक घोषित किया गया था। मलबा हटाने के

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिए कि वे छात्रों के रहने की जगह के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित करें और छात्रावास की सुविधाएं विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करें। उपराज्यपाल संधू ने इस बाबत लोक निवास में डीडीए अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में वैकल्पिक आवास सुविधाओं के विकल्पों की गहन समीक्षा भी की।

नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल नोटिस के बाद भी नहीं रुका अवैध निर्माण

ललिता पार्क में पांच मंजिला इमारत पर आठ माह से कार्रवाई नहीं। न्यू सीलमपुर में नोटिस के बावजूद चार मंजिल तक पहुंचा निर्माण।

बाद डीएमसी अधिनियम-1957 की धारा 346 का घोर उल्लंघन पाया। इसके चलते भवन को खाली करने का नोटिस शाहदरा दक्षिणी जोन के सहायक अभियंता (भवन)-द्वितीय की ओर से 29 जनवरी, 2026 को जारी किया गया। जबकि, एमसीडी की तरफ से इस इमारत को तीन दिसंबर 2025 को अवैध निर्माण में बुक किया गया था। बावजूद इसके निगम अधिकारियों ने आठ माह बीतने के बाद भी इस पांच मंजिला भवन पर कोई

प्रदूषण से निपटने की तैयारी संवेदनशील क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारी संभालेंगे कमान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 सितंबर ।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को कार्यवाही के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपराज्‍यपाल संधू और मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता को अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 13 जिलों में फैले 47 संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के उपायों के प्रभावी क्रियान्‍वयन के लिए अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्‍तर के 13 वरिष्‍ठ अधिकारियों को इसका प्रभारी बनाया गया है।

उपराज्‍यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को कार्यवाही के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपराज्‍यपाल संधू और मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता को अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 13 जिलों में फैले 47 संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के उपायों के प्रभावी क्रियान्‍वयन के लिए अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्‍तर के 13 वरिष्‍ठ अधिकारियों को इसका प्रभारी बनाया गया है।

उग्र सीमा 17 से 22 साल, जबकि स्नातकोत्तर छात्रों के लिए यह सीमा 25 साल तक है। नामांकन पत्र 500 रुपए के हलफनामों के साथ गुरुवार को दोपहर तीन बजे तक ही जमा किया जा सकेगा।

नई दिल्ली

मौसम

तापमान
अधिकतम- 36.1

न्यूनतम- 27.0

नई दिल्ली

सूर्योदय- 06:03

सूर्यास्त- 06:34

जनसत्ता

10 सितंबर, 2026

एमसीडी ने बुधवार को राजधानी में संचालित पीजी आवासीय भवनों का व्यापक सर्वेक्षण भी किया। अब तक किए गए सर्वेक्षण में करीब 1,243 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं। इन भवनों में लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। एमसीडी अब सर्वेक्षण के आधार पर संवेदनशील पीजी भवनों की पहचान और उनका वर्गीकरण कर रहा है। भवनों को उनकी स्थिति के अनुसार दृष्टिगत रूप से सुरक्षित, दृष्टिगत रूप से मरम्मत योग्य, मामूली मरम्मत आवश्यक, व्यापक मरम्मत आवश्यक और दृष्टिगत रूप से संवेदनशील या खतरनाक जैसी श्रेणियों में बांटा जा रहा है।

अभियान के दौरान सुरक्षा के लिहाज से इमारत को जैक पर रोककर रखा गया था। बुधवार को चलाए गए प्रवर्तन अभियान के दौरान संपत्ति संख्या 1412, गली गोंडनी वाली, कूचा चेलन, जामा मस्जिद में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

छात्रावास के लिए जमीन तलाश करेगा डीडीए

उपराज्यपाल ने कहा कि डीडीए को पीजी के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज करने के साथ साथ कार्ययोजना तैयार करने और छात्रावास सुविधाओं के विकास के लिए नए मास्टर प्लान के प्रावधानों को लेकर विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। संधू ने कहा कि हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित, किरायाती और सम्मानजनक आवास सुविधा उपलब्ध हो।

इसी तरह, न्यू सीलमपुर की जी-31 संपत्ति, जिसमें सरकारी जमीन पर कच्चे का मामला भी शामिल है, में भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर अवैध निर्माण के चलते अप्रैल 2025 में कार्य रोकने का नोटिस दिया गया था। कार्रवाई नहीं होने पर आठ अगस्त, 2025 को दूसरा नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद निर्माण नहीं रुका और अब भवन चार मंजिल तक तैयार हो चुका है।

हर स्थल के तीन किलोमीटर दायरे के लिए बनेगी विस्तृत कार्ययोजना।

दिल्ली के 13 जिलों में फैले 47 संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 13 वरिष्ठ अधिकारियों को इसका प्रभारी बनाया गया है।

नई दिल्ली

मौसम

तापमान
अधिकतम- 36.1

न्यूनतम- 27.0

नई दिल्ली

सूर्योदय- 06:03

सूर्यास्त- 06:34

जनसत्ता

10 सितंबर, 2026

एमसीडी ने बुधवार को राजधानी में संचालित पीजी आवासीय भवनों का व्यापक सर्वेक्षण भी किया। अब तक किए गए सर्वेक्षण में करीब 1,243 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं। इन भवनों में लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। एमसीडी अब सर्वेक्षण के आधार पर संवेदनशील पीजी भवनों की पहचान और उनका वर्गीकरण कर रहा है। भवनों को उनकी स्थिति के अनुसार दृष्टिगत रूप से सुरक्षित, दृष्टिगत रूप से मरम्मत योग्य, मामूली मरम्मत आवश्यक, व्यापक मरम्मत आवश्यक और दृष्टिगत रूप से संवेदनशील या खतरनाक जैसी श्रेणियों में बांटा जा रहा है।

अभियान के दौरान सुरक्षा के लिहाज से इमारत को जैक पर रोककर रखा गया था। बुधवार को चलाए गए प्रवर्तन अभियान के दौरान संपत्ति संख्या 1412, गली गोंडनी वाली, कूचा चेलन, जामा मस्जिद में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

नई दिल्ली

मौसम

तापमान
अधिकतम- 36.1

न्यूनतम- 27.0

नई दिल्ली

सूर्योदय- 06:03

सूर्यास्त- 06:34

जनसत्ता

10 सितंबर, 2026

एमसीडी ने बुधवार को राजधानी में संचालित पीजी आवासीय भवनों का व्यापक सर्वेक्षण भी किया। अब तक किए गए सर्वेक्षण में करीब 1,243 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं। इन भवनों में लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। एमसीडी अब सर्वेक्षण के आधार पर संवेदनशील पीजी भवनों की पहचान और उनका वर्गीकरण कर रहा है। भवनों को उनकी स्थिति के अनुसार दृष्टिगत रूप से सुरक्षित, दृष्टिगत रूप से मरम्मत योग्य, मामूली मरम्मत आवश्यक, व्यापक मरम्मत आवश्यक और दृष्टिगत रूप से संवेदनशील या खतरनाक जैसी श्रेणियों में बांटा जा रहा है।

उपराज्‍यपाल ने कहा कि डीडीए को पीजी के लिए उपयुक्‍त जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज करने के साथ साथ कार्ययोजना तैयार करने और छात्रावास सुविधाओं के विकास के लिए नए मास्‍टर प्लान के प्रावधानों को लेकर विश्‍वविद्यालय अधि्‍कारियों के साथ चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। संधू ने कहा कि हमारा ध्‍यान यह सुनिश्चित करने पर है कि दिल्‍ली में छात्रों को सुरक्षित, किरायाती और सम्‍मानजनक आवास सुविधा उपलब्‍ध हो।

उग्र सीमा 17 से 22 साल, जबकि स्नातकोत्तर छात्रों के लिए यह सीमा 25 साल तक है। नामांकन पत्र 500 रुपए के हलफनामों के साथ गुरुवार को दोपहर तीन बजे तक ही जमा किया जा सकेगा।

नई दिल्ली

मौसम

तापमान
अधिकतम- 36.1

न्यूनतम- 27.0

नई दिल्ली

सूर्योदय- 06:03

सूर्यास्त- 06:34

जनसत्ता

10 सितंबर, 2026

हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और डीयू से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 9 सितंबर (भाषा)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एनएसयूआइ अध्यक्ष की उस याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा, जिसमें संस्थान के सभी कालेजों में छात्रावास सुविधा की मांग की गई थी। इस जनहित याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किरायाती और पर्याप्त संस्थागत छात्रावास सुविधा की 'लंबे समय से चली आ रही कमी' का मुद्दा उठाया गया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष विनोद जांखड़ द्वारा यह याचिका छह सितंबर को सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने की घटना के बाद दायर की गई थी। इस इमारत का इस्तेमाल छात्रों के निजी 'पेगंग गेस्ट' (पीजी) के तौर पर किया जा रहा था। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की और इसे इमारत गिरने की घटना से जुड़े एक और मामले के साथ जोड़ दिया। जनहित याचिका को एक बहुत गंभीर मुद्दा मानते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने बिना किसी वजह के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को याचिका में पक्ष क्यों बनाया और उन्हें इसे हटाने के लिए कहा। याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 104 साल बीतने और छात्रों की संख्या व भौगोलिक विस्तार में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, रहन-सहन की सुविधा उस अनुपात में विकसित नहीं हुई है। इसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में कालेजों में कोई छात्रावास सुविधा नहीं है, जबकि जिन कालेजों में छात्रावास हैं, वहां सीटों की संख्या असल जरूरत के मुकाबले बहुत कम है।

विज्ञापनसंख्या. 95/2026
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
में
निदेशक (तकनीकी)
पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
29/09/2026 (15:00 बजे तक) है।
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को
लोक उद्यम चयन बोर्ड के ऑनलाइन सिस्टम में अप्रेशित करने की अंतिम तिथि
08/10/2026 (17:00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट https://www.pesb.gov.in में लॉग इन करें।
नोडल अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारियों के फंजीकरण के लिए
लिंक पीईएसबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

केनरा बैंक Canara Bank
रिजिस्टर सिंडिकेट
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र.का., 112, जे.सी. रोड, बेंगलूरु- 560 002
भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण और अमूर्तीकरण के लिए विशेष विंडो
सेबी के परिपत्र संख्या प्र.का/38/13/11(2)2026-एमआरएसडी-पीओडी/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुपालन में सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय/विक्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण एवं विमूर्तीकरण (डीमैट) को सुगम बनाने हेतु 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष अवसर प्रदान किया गया है। यह सुविधा उन अंतरण विलेखों पर लागू होगी, जो 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व प्रस्तुत किए गए थे, किन्तु दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत, लौटाए गए अथवा लंबित रह गए थे। निवेशक आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना अनुरोध 04 फरवरी, 2027 तक बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अधिकर्ता (आरटीए) के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।
आरटीए का विवरण इस प्रकार है:-
केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
(केनरा बैंक इकाई)
सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32, गाचीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नान्दकरामगुड़ा, हैदराबाद – 500032
टोल-फ्री नं.: 1800-309-4001
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
हम सभी शेयरधारकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं) या आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं) के साथ पैन, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण सहित केवाईसी विवरण को अद्यतन करें, ताकि संचार में आसानी और लाभार्श के निर्बाध भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके।
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र जमा करके अपने शेयर डीमैट करा लें।
बैंक ने 02 अप्रैल, 2026, 09 जून, 2026 और 22 जुलाई, 2026 को समाचार पत्र में भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण और विमूर्तीकरण के लिए विशेष विंडो पर विज्ञापन जारी किए थे।
04 फरवरी, 2027 के बाद प्रस्तुत भौतिक प्रतिभूतियों के अनुरोधों का अंतरण एवं विमूर्तीकरण बैंक/आरटीए द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हस्ताक्षरित/-
सतोष कुमार बारिक
कंपनी सचिव

